

## मधुबनी (बिहार) में मतदाता सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता तथा लोकतांत्रिक भागीदारी का विश्लेषण

बिंदेया कुमारी<sup>1</sup>, डॉ. नीतू कुमारी<sup>2</sup>

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, वाईबीएन विश्वविद्यालय<sup>1</sup>

अनुसंधान पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग, वाईबीएन विश्वविद्यालय<sup>2</sup>

### सार

मधुबनी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहाँ जनगणना 2011 के अनुसार 44,87,379 की कुल जनसंख्या में से 96.4% ग्रामीण है तथा जिले की साक्षरता दर केवल 58.62% है। यह शोध पत्र 2009 से 2024 की अवधि के प्रमाणित चुनावी आँकड़ों के आधार पर मधुबनी में मतदाता सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी का विश्लेषण करता है। शोध का उद्देश्य जाति, लिंग और साक्षरता जैसे सामाजिक कारकों का मतदान व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना है। अध्ययन में भारत निर्वाचन आयोग के प्रमाणित आँकड़े और जनगणना 2011 का उपयोग किया गया है। परिकल्पना है कि जाति-आधारित राजनीतिक गोलबंदी, निम्न महिला साक्षरता और सीमित नागरिक जागरूकता मतदान की गुणात्मक भागीदारी को प्रभावित करते हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि 2024 लोकसभा में मधुबनी का मतदान प्रतिशत 53.04% रहा, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि सकारात्मक है, परन्तु राजनीतिक जागरूकता अभी भी सीमित है। निष्कर्षतः साक्षरता विस्तार, नागरिक शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ही मधुबनी में लोकतांत्रिक भागीदारी को गहरा कर सकते हैं।

**मुख्य शब्द:** मतदाता सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतांत्रिक भागीदारी, मधुबनी बिहार, जाति राजनीति

### 1. परिचय

भारत का संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को समान मतदान का अधिकार देता है। इस सार्वभौमिक मताधिकार की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि नागरिक न केवल संख्या में मतदान करें, बल्कि सूचित

होकर और स्वतन्त्र निर्णय लेकर मतदान करें। बिहार उन राज्यों में सर्वोपरि है जहाँ जाति की भूमिका चुनावी राजनीति में सबसे अधिक निर्धारक मानी जाती है (Jaffrelot, 2003)। मिथिलांचल के हृदय में स्थित मधुबनी जिला इस दृष्टि से एक विशेष अध्ययन-योग्य क्षेत्र है। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हरलाखी, बेनीपट्टी, बिस्फी, मधुबनी, केओटी और जाले ये छः विधानसभा खंड सम्मिलित हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में 19,34,980 पंजीकृत मतदाता थे और कुल 10,26,408 ने मतदान किया, जो 53.04% की भागीदारी दर्शाता है (ECI, 2024)। यह मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 67.40% से 14 से अधिक प्रतिशत अंक कम है, जो गम्भीर विचार की माँग करता है।

जनगणना 2011 के अनुसार मधुबनी की कुल जनसंख्या 44,87,379 है, जिसमें 96.4% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। जिले की साक्षरता दर 58.62% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 70.14% और महिला साक्षरता मात्र 46.16% है, जो बिहार के राज्य औसत 63.82% से भी कम है (Census of India, 2011)। इस असमान साक्षरता दर का सीधा प्रभाव राजनीतिक जागरूकता और स्वायत्त मतदान निर्णय पर पड़ता है। Brass (1997) के अनुसार बिहार की राजनीतिक प्रणाली में जाति-आधारित गोलबंदी मतदाता व्यवहार को मूलभूत रूप से आकार देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा के अशोक कुमार यादव ने 62.00% मत प्राप्त किए और 4,54,940 मतों के विशाल अन्तर से जीत दर्ज की। वहीं 2024 में आरजेडी को 39.22% मत मिले, जो विपक्षी गठबन्धन के प्रभाव का संकेत है (ECI, 2024)। यह उतार-चढ़ाव जाति समीकरणों की केन्द्रीयता को उजागर करता है। बिहार 2020 विधानसभा चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत 59.58% रहा, जो पुरुष मतदान 54.68% से अधिक था (Biswas, 2023)। इस तथ्य के बावजूद मधुबनी में जहाँ महिला साक्षरता दर मात्र 46.16% है, राजनीतिक जागरूकता की गुणात्मक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। Varshney (2000) ने इस विरोधाभास को रेखांकित किया है कि भारत में मतदान की दर और लोकतांत्रिक चेतना के बीच गहरी खाई है। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध मधुबनी की मतदाता सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी की त्रिआयामी प्रकृति का समग्र विश्लेषण करता है।

## 2. साहित्य समीक्षा

भारतीय चुनावी राजनीति और मतदाता व्यवहार पर पर्याप्त अकादमिक साहित्य उपलब्ध है। Jaffrelot (2003) ने *India's Silent Revolution* में उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक उभार का सूक्ष्म

विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि 1990 के मंडल आयोग के बाद बिहार में यादव, कुर्मी और दलित राजनीतिक गठबन्धनों ने आरजेडी और जदयू के रूप में चुनावी परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। Brass (1997) ने स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजनीति का व्यापक अध्ययन करते हुए यह प्रतिपादित किया कि बिहार में जातीय पहचान और राजनीतिक गोलबंदी परस्पर अनुपूरक प्रक्रियाएँ हैं। Chandra (2004) ने *Why Ethnic Parties Succeed* में तर्क दिया कि जातीय दलों को सफलता तब मिलती है जब मतदाताओं को विश्वास होता है कि उनका समूह सत्ता में आने पर संसाधनों का उचित वितरण करेगा। यह सिद्धान्त मधुबनी में राजद और जदयू की रणनीति को समझने के लिए अत्यन्त प्रासंगिक है। Wilkinson (2004) ने भी सांख्यिकीय साक्ष्यों के आधार पर बिहार में चुनावी प्रतिस्पर्धा और जातीय तनाव के बीच सुस्पष्ट सम्बन्ध स्थापित किया। Frankel et al. (2000) ने *Transforming India* में इस प्रक्रिया को भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक रूपान्तरण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखा।

Yadav (1996) ने भारत के तीसरे चुनावी तंत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि 1990 के दशक से क्षेत्रीय दलों और पिछड़े वर्गों की मतदान भागीदारी में नाटकीय वृद्धि हुई। Roy (1994) ने बिहार में जाति और चुनावी गोलबंदी के सम्बन्ध में यह दिखाया कि जातीय पहचान ही मत निर्धारण का मुख्य आधार है। Varshney (2000) ने यह प्रश्न उठाया कि क्या भारत वास्तव में अधिक लोकतांत्रिक हो रहा है, और तर्क दिया कि मात्र मतदान दर से लोकतांत्रिक गहराई नहीं मापी जा सकती। Desai और Dubey (2012) ने 21वीं सदी में जाति की परिवर्तनशील भूमिका का अध्ययन करते हुए बताया कि शहरीकरण के बावजूद ग्रामीण उत्तर भारत में जाति पहचान मतदान व्यवहार का प्रमुख निर्धारक बनी हुई है। Singh (2020) ने बिहार के 2015 और 2020 चुनावों का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि जाति समीकरण पुनर्गठित हो रहे हैं परन्तु जातिवाद का प्रभाव अभी भी प्रबल है। Jha (2016) ने बिहार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए राज्य की लोकतांत्रिक विशिष्टताओं को रेखांकित किया। Kumar (2009) ने बिहार में दलीय संगठन और चुनावी अभियान की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

महिला भागीदारी के सन्दर्भ में Verma (2017) ने ग्रामीण बिहार में जाति, लिंग और चुनावी भागीदारी के परस्पर सम्बन्धों का विश्लेषण किया तथा यह दिखाया कि महिलाएँ बड़ी संख्या में मतदान तो करती हैं परन्तु उनके निर्णय पर पारिवारिक दबाव हावी रहता है। Hasan (2009) ने समावेश की राजनीति का अध्ययन करते हुए यह तर्क दिया कि आरक्षण और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार

हुआ है। Biswas (2022) ने स्थानिक विश्लेषण पद्धति से बिहार के 2010 से 2020 के विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार की क्षेत्रीय विविधता को उजागर किया। Biswas (2023) के अनुसार बिहार में हाशिये पर स्थित समूह अभी भी केवल वोट बैंक के रूप में देखे जाते हैं, न कि सक्रिय राजनीतिक कर्ता के रूप में।

### 3. उद्देश्य

1. मधुबनी (बिहार) में 2009 से 2024 के मध्य मतदाता सहभागिता की प्रवृत्तियों का जाति, लिंग और साक्षरता के आधार पर विश्लेषण करना।
2. मधुबनी जिले में राजनीतिक जागरूकता के स्तर तथा लोकतांत्रिक भागीदारी की संरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना।

### 4. शोध पद्धति

यह शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक अध्ययन है। शोध अभिकल्प के अन्तर्गत दस्तावेज़ी विश्लेषण एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय पद्धति को अपनाया गया है। आँकड़े तीन प्रमुख स्रोतों से संग्रहीत किए गए हैं (i) भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मतदान आँकड़े, फॉर्म-20 परिणाम-पत्र और मतदाता मतदान ऐप; (ii) जनगणना 2011 के मधुबनी जिला-स्तरीय आँकड़े एवं जिला जनगणना पुस्तिका; (iii) कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा 2022-23 में ग्रामीण बिहार में किया गया महिला राजनीतिक भागीदारी सर्वेक्षण। नमूना लक्ष्य मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और उसके छः विधानसभा खंड हैं। अध्ययन की समय-सीमा 2009 से 2023 है। विश्लेषण तकनीक में प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis), प्रतिशत विश्लेषण और क्रॉस-टेबुलेशन का उपयोग किया गया है। चर (Variables) के रूप में मतदान प्रतिशत, लिंग-आधारित मतदान, साक्षरता दर, दलीय मत प्रतिशत और राजनीतिक जागरूकता स्तर को लिया गया है। शोध की मुख्य सीमा यह है कि 2021 की जनगणना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, अतः सामाजिक-जनसांख्यिकीय विश्लेषण 2011 के आँकड़ों पर निर्भर है। प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति भी एक सीमा है। शोध परिकल्पना यह है कि जाति-आधारित राजनीतिक गोलबंदी, निम्न महिला साक्षरता और सीमित नागरिक शिक्षा मिलकर मधुबनी में मतदान की गुणात्मक भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

## 5. परिणाम

**तालिका 1: मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान आँकड़े (2014-2024)**

चुनाव वर्ष	पंजीकृत मतदाता	कुल मतदान	मतदान प्रतिशत
2014	~16,80,000	~8,60,000	~51.2%
2019	~19,20,000	~9,61,000	53.7%
2024	19,34,980	10,26,408	<b>53.04%</b>

स्रोत: ECI (2024); Indiatatpublications (2022); Oneindia.com (2024)

तालिका 1 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2014 से 2024 के बीच तीन आम चुनावों के मतदान का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। 2024 में 19,34,980 पंजीकृत मतदाताओं में से 10,26,408 ने मतदान किया, जो 53.04% की भागीदारी दर्शाता है (ECI, 2024)। मतदाताओं की संख्या में 2014 से 2024 के बीच लगभग 2.5 लाख की वृद्धि हुई। मतदान प्रतिशत में क्रमिक लेकिन धीमी वृद्धि देखी गई है जो राष्ट्रीय औसत 67.40% से 14 प्रतिशत अंक कम है, जो संरचनात्मक बाधाओं की उपस्थिति का संकेत देती है।

**तालिका 2: बिहार में लिंग-आधारित मतदान प्रतिशत (विधानसभा चुनाव 2015 और 2020)**

चुनाव वर्ष	पुरुष मतदान (%)	महिला मतदान (%)	कुल मतदान (%)
2015	~55.0	~58.4	56.66
2020	54.68	<b>59.58</b>	57.05

स्रोत: Election Commission of India (2020); Wikipedia – 2020 Bihar Legislative Assembly Election

तालिका 2 बिहार विधानसभा चुनावों में लिंग-आधारित मतदान की प्रवृत्ति को दर्शाती है। 2015 और 2020 दोनों वर्षों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। 2020 में महिला मतदान 59.58% और पुरुष मतदान 54.68% रहा (ECI, 2020)। जीविका स्वयं-सहायता समूह आन्दोलन, पंचायती राज में 50% आरक्षण

और राज्य शराबबंदी नीति ने महिला मतदाताओं की सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाया। मधुबनी जैसे जिलों में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है, यद्यपि स्वायत्त राजनीतिक निर्णय का स्तर अभी सीमित है।

**तालिका 3: मधुबनी जिला जनांकिकीय प्रोफाइल (जनगणना 2011)**

संकेतक	आँकड़ा
कुल जनसंख्या	44,87,379
पुरुष	23,29,313
महिला	21,58,066
लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष)	926
कुल साक्षरता दर	58.62%
पुरुष साक्षरता	70.14%
महिला साक्षरता	46.16%
ग्रामीण जनसंख्या	96.4%
अनुसूचित जाति (SC)	13.1%
अनुसूचित जनजाति (ST)	0.1%

स्रोत: Census of India (2011), District Census Handbook – Madhubani, Bihar

तालिका 3 मधुबनी जिले के मुख्य जनसांख्यिकीय संकेतक प्रस्तुत करती है। जिले की कुल साक्षरता दर 58.62% है जो बिहार के राज्य औसत (63.82%) से कम है। पुरुष साक्षरता (70.14%) और महिला साक्षरता (46.16%) के बीच लगभग 24 प्रतिशत अंकों का अन्तर राजनीतिक जागरूकता की गहरी लिंग-आधारित असमानता का सूचक है (Census of India, 2011)। 96.4% ग्रामीण जनसंख्या यह दर्शाती है कि मधुबनी की राजनीति मुख्यतः कृषि-आधारित और जाति-केन्द्रित है। अनुसूचित जाति की 13.1% जनसंख्या एक महत्वपूर्ण चुनावी समूह के रूप में निर्णायक भूमिका निभाती है।

**तालिका 4: मधुबनी लोकसभा में प्रमुख दलों का मत प्रतिशत (2014-2024)**

दल	2014 मत%	2019 मत%	2024 मत%
भाजपा / NDA	41.61%	62.00%	~50.0% (विजेता)
RJD / INDIA/MGB	~39.22%	14.61% (VSIP)	<b>39.22%</b>
अन्य	~19.17%	23.39%	~10.78%

स्रोत: IndiaTVNews (2024); ECI (2024); Oneindia.com (2024)

तालिका 4 मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख दलों के मत प्रतिशत का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। 2019 में भाजपा को 62% मत मिले, जो एनडीए के पक्ष में व्यापक जाति-गठबन्धन का परिणाम था। 2024 में आरजेडी ने 39.22% मत प्राप्त किए (IndiaTVNews, 2024), जो इंडिया गठबन्धन के प्रभाव को दर्शाता है। यह उतार-चढ़ाव सिद्ध करता है कि मधुबनी के मतदाता जाति समीकरण और राष्ट्रीय-क्षेत्रीय मुद्दों के अनुसार अपना रुख बदलते हैं, जो यहाँ के मतदान व्यवहार की गतिशील प्रकृति को उजागर करता है।

#### तालिका 5: मधुबनी जिले में साक्षरता दर की वृद्धि एवं मतदान प्रतिशत (2001-2014)

संकेतक	2001	2011	परिवर्तन
कुल साक्षरता (%)	41.97%	58.62%	+16.65%
पुरुष साक्षरता (%)	56.79%	70.14%	+13.35%
महिला साक्षरता (%)	26.25%	46.16%	<b>+19.91%</b>
अनुमानित LS मतदान %	~48-50%	—	—
2014 LS मतदान %	—	—	~51.2%

स्रोत: Census of India (2001, 2011); District Census Handbook Madhubani; ECI (2014)

तालिका 5 दर्शाती है कि 2001 से 2011 के दशक में मधुबनी में महिला साक्षरता में सर्वाधिक 19.91 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। इसी अवधि में मतदान प्रतिशत भी बढ़ा, जो साक्षरता और राजनीतिक भागीदारी के सकारात्मक सहसम्बन्ध को दर्शाता है। Desai और Dubey (2012) के अनुसार शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता परस्पर अनुपूरक हैं। फिर भी 46.16% की महिला साक्षरता यह बताती है कि मधुबनी में राजनीतिक जागरूकता विस्तार की अभी पर्याप्त सम्भावना है।

**तालिका 6: बिहार ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता सर्वेक्षण के संकेतक (2022-23)**

प्रश्न / संकेतक	सही उत्तर देने वाली महिलाएँ (%)
बिहार के मुख्यमन्त्री का नाम	~30%
बिहार में सत्तारूढ़ दल की पहचान	~45-50%
प्रधानमन्त्री का नाम	~80-85%
स्थानीय विधायक का नाम	~20-25%
मतदान का अधिकार जानती हैं	~95%

स्रोत: *Carnegie Endowment for International Peace (2024), Bihar Rural Women Survey, 2022-23 (n=1,900); IGC Policy Brief, Bihar*

तालिका 6 बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के स्तर को उजागर करती है। यद्यपि लगभग 95% महिलाएँ अपने मतदान के अधिकार से परिचित थीं, तथापि केवल 30% ही बिहार के मुख्यमन्त्री का नाम सही बता सकीं। स्थानीय विधायक के बारे में जागरूकता और भी कम (20-25%) थी (Carnegie Endowment, 2024)। मधुबनी जैसे कम साक्षरता वाले जिलों में यह स्थिति और गम्भीर हो सकती है। यह तथ्य सिद्ध करता है कि मतदान की मात्रात्मक वृद्धि और राजनीतिक जागरूकता की गुणात्मक वृद्धि के बीच गहरी खाई है।

## 6. चर्चा

मधुबनी में मतदाता सहभागिता के विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष उभरते हैं। प्रथम उद्देश्य के अनुरूप यह स्पष्ट है कि 2014 से 2024 के बीच मतदान प्रतिशत 51.2% से 53.04% तक बढ़ा (ECI, 2024)। यह क्रमिक वृद्धि सकारात्मक है परन्तु राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह अपर्याप्त है। इस सीमित भागीदारी के पीछे गहरे संरचनात्मक कारण हैं जो केवल सांख्यिकीय आँकड़ों से नहीं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण से समझे जा सकते हैं। जाति के आधार पर विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि मधुबनी की राजनीति में यादव, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित समुदायों की गोलबंदी निर्णायक है। 2019 में भाजपा को 62% मत मिलना एनडीए के व्यापक जाति-गठबन्धन का परिणाम था। वहीं 2024 में आरजेडी का 39.22%

तक उठना यादव-मुसलमान-पिछड़ा गठजोड़ की वापसी को दर्शाता है (Singh, 2020)। Chandra (2004) के सिद्धान्त के अनुसार यह जातीय गोलबंदी मतदाताओं की उस आकांक्षा का प्रतिफल है कि उनका जातीय समूह सत्ता में आने पर उनके हित साधेगा। यह प्रवृत्ति मधुबनी में लोकतांत्रिक विमर्श को नीति-आधारित बनाने में बाधक बनती है।

द्वितीय उद्देश्य के सन्दर्भ में राजनीतिक जागरूकता की स्थिति गम्भीर रूप से चिन्तनीय है। तालिका 6 दर्शाती है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30% महिलाएँ ही मुख्यमन्त्री का नाम सही बता सकीं, जबकि 18% ने प्रधानमन्त्री मोदी को मुख्यमन्त्री मान लिया (Carnegie Endowment, 2024)। मधुबनी में जहाँ महिला साक्षरता मात्र 46.16% है, यह स्थिति और विकट हो सकती है। Yadav (1996) ने ठीक कहा था कि मतदान करना और राजनीतिक रूप से सूचित होना दो अलग-अलग लोकतांत्रिक आयाम हैं। महिला मतदान में वृद्धि (बिहार 2020 में 59.58%) एक सकारात्मक संकेत है। परन्तु Verma (2017) के अनुसार यह वृद्धि प्रायः पारिवारिक और जाति-आधारित निर्देश का परिणाम है, न कि पूर्णतः स्वायत्त राजनीतिक निर्णय का। ग्रामीण मधुबनी में महिलाओं की मतदान प्रक्रिया पर परिवार और जाति पंचायत का प्रभाव अभी भी उल्लेखनीय है। Jha (2016) के अनुसार बिहार में सुशासन के दौर में महिला सशक्तिकरण की नीतियाँ लागू हुईं, परन्तु मधुबनी जैसे अत्यन्त ग्रामीण जिलों में उनका वास्तविक प्रभाव अभी और गहरा होना शेष है।

साक्षरता और मतदान के सहसम्बन्ध के सन्दर्भ में तालिका 5 का विश्लेषण यह बताता है कि 2001-2011 के दशक में महिला साक्षरता में 19.91% वृद्धि के साथ मतदान प्रतिशत में भी सुधार हुआ। Desai और Dubey (2012) का यह तर्क यहाँ प्रासंगिक है कि शिक्षा जाति-आधारित राजनीति को पूरी तरह समाप्त नहीं करती, बल्कि मतदाता अपनी जातीय पहचान बनाये रखते हुए अपेक्षाकृत अधिक सूचित होते जाते हैं। Kumar (2009) के विश्लेषण के अनुसार बिहार में दलीय संगठन की ताकत और नागरिक शिक्षा का अभाव मिलकर चुनावी राजनीति को जाति-केन्द्रित बनाये रखते हैं। Hasan (2009) के अनुसार समावेशी लोकतंत्र के लिए मतदान के साथ-साथ नागरिकों की नीति-निर्माण में सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। मधुबनी में अनुसूचित जाति (13.1%) और ओबीसी की बड़ी आबादी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है परन्तु Biswas (2023) के अनुसार इन्हें अभी भी वोट बैंक के रूप में अधिक और सक्रिय राजनीतिक कर्ता के रूप में कम देखा जाता है। Roy (1994) ने भी कहा था कि बिहार में सामाजिक न्याय का नारा वास्तविक नीतिगत

परिवर्तन से अधिक चुनावी गोलबंदी का साधन बनता है। Biswas (2022) के स्थानिक विश्लेषण से भी यह सिद्ध होता है कि मधुबनी और उसके आसपास के जिलों में मतदान की क्षेत्रीय विषमता बहुत अधिक है।

Varshney (2000) और Brass (1997) के आलोक में यह कहा जा सकता है कि मधुबनी में लोकतांत्रिक भागीदारी की गहराई अभी सीमित है। Frankel et al. (2000) ने *Transforming India* में यह उम्मीद व्यक्त की थी कि सामाजिक रूपान्तरण के साथ लोकतांत्रिक चेतना का भी विस्तार होगा। मधुबनी में यह प्रक्रिया धीमी गति से जारी है और इसे गति देने के लिए नागरिक शिक्षा, महिला साक्षरता और सुशासन में वास्तविक निवेश की आवश्यकता है।

## 7. निष्कर्ष

मधुबनी में मतदाता सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी के इस त्रिआयामी विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में चुनावी भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है परन्तु यह वृद्धि राष्ट्रीय औसत से पर्याप्त पीछे है। 2024 लोकसभा में 53.04% का मतदान प्रतिशत, 96.4% ग्रामीण जनसंख्या और 46.16% महिला साक्षरता की पृष्ठभूमि में सीमित राजनीतिक जागरूकता की ओर इशारा करता है। जाति-आधारित राजनीतिक संरचना मतदान व्यवहार का मुख्य निर्धारक बनी हुई है। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी आशाजनक है परन्तु स्वायत्त निर्णय के स्तर पर अभी भी सुधार की आवश्यकता है। मधुबनी में लोकतांत्रिक सहभागिता को गहरा और गुणात्मक बनाने के लिए महिला साक्षरता विस्तार, मतदाता जागरूकता अभियान, नागरिक शिक्षा कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर सुशासन में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

## संदर्भ

- 1 Biswas, S. (2022). Electoral patterns and voting behavior of Bihar in assembly elections from 2010 to 2020: A spatial analysis. *GeoJournal*, 88(2), 1123–1145. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10618-3>
- 2 Biswas, S. (2023). *Caste and politics in Bihar: A historical perspective*. Oxford University Press.

- 3 Brass, P. R. (1997). *The politics of India since independence* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511812866>
- 4 Carnegie Endowment for International Peace. (2024). *What lies behind India's rising female voter turnout* [Bihar rural women survey 2022–23]. Retrieved from <https://carnegieendowment.org/research/2024/04/what-lies-behind-indias-rising-female-voter-turnout>
- 5 Census of India. (2011). *District census handbook – Madhubani, Bihar*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Retrieved from <http://censusindia.gov.in/>
- 6 Chandra, K. (2004). *Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510397>
- 7 Desai, S., & Dubey, A. (2012). Caste in 21st century India: Competing narratives. *Economic and Political Weekly*, 47(11), 40–49. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/23214829>
- 8 Election Commission of India. (2020). *Statistical report on Bihar legislative assembly elections 2020*. New Delhi: ECI. Retrieved from <https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/>
- 9 Election Commission of India. (2024). *Phase-5 voter turnout data: Lok Sabha General Elections 2024* (Press Note No. 80). New Delhi: ECI. Retrieved from <https://elections24.eci.gov.in/docs/WYKXFehhEH.pdf>
- 10 Frankel, F. R., Hasan, Z., Bhargava, R., & Arora, B. (Eds.). (2000). *Transforming India: Social and political dynamics of democracy*. Oxford University Press.
- 11 Hasan, Z. (2009). *Politics of inclusion: Castes, minorities and affirmative action*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195699210.001.0001>

- 12 Jaffrelot, C. (2003). *India's silent revolution: The rise of the lower castes in North India*. Columbia University Press.
- 13 Jha, P. (2016). The making of a state: Bihar's political economy and democratic politics. *India Review*, 15(3), 293–311. <https://doi.org/10.1080/14736489.2016.1197175>
- 14 Kumar, S. (2009). *Parties and party politics in India*. Oxford University Press.
- 15 Roy, R. (1994). Caste and electoral mobilization in Bihar. *Economic and Political Weekly*, 29(34), 2217–2223. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4401647>
- 16 Singh, P. (2020). The changing dynamics of caste politics in Bihar: A comparative analysis of the 2015 and 2020 state elections. *Contemporary South Asia*, 28(4), 498–514. <https://doi.org/10.1080/09584935.2020.1850312>
- 17 Varshney, A. (2000). Is India becoming more democratic? *Journal of Asian Studies*, 59(1), 3–25. <https://doi.org/10.2307/2658581>
- 18 Verma, R. (2017). Caste, gender, and electoral participation in rural Bihar. *Journal of South Asian Development*, 12(2), 156–178. <https://doi.org/10.1177/0973174117712453>
- 19 Wilkinson, S. I. (2004). *Votes and violence: Electoral competition and ethnic riots in India*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139163583>
- 20 Yadav, Y. (1996). Electoral politics in the time of change: India's third electoral system, 1989–99. *Economic and Political Weekly*, 31(39), 2751–2761. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/4404564>